

HINDI FILE



DREAM
FOR NATION



DARE
TO SERVE



DELIVER
WITH INTEGRITY

DAILY PRACTICE QUESTIONS

BEST FOR UPSC | UP PCS EXAM

DATE : **SEPTEMBER 25, 2026**



Comprehensive
Coverage



Exam-Focused
Analysis



Concept Clarity
& Insights



Practice MCQs
with Explanation



Daily Updates,
Better Results



CONTACT INFO:

+91 92896 33341 | +91 96679 33341



EMAIL ID:

info@sixsigmaias.com



WEB PAGE:

www.sixsigmaias.com



ADDRESS:

C-6, GROUND FLOOR, SECTOR 2,
NEAR SECTOR 15 METRO STATION, NOIDA – 201301, UTTAR PRADESH

दैनिक अभ्यास प्रश्न - स्थैतिक भाग से

प्रश्न 1. भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. प्रस्तावना में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "भारत के लोग" का तात्पर्य है कि संप्रभुता अविभाज्य है और इसे संवैधानिक रूप से अलग (alienated) नहीं किया जा सकता है।
2. संविधान में संशोधन करने का अधिकार अंततः उसी घटक शक्ति (constituent power) से प्रवाहित होता है जिसने 1949 में संविधान को अपनाया था।

उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

- (a) केवल एक
- (b) दोनों
- (c) कोई भी नहीं
- (d) संविधान से निर्धारित नहीं किया जा सकता

उत्तर: (b) दोनों

विस्तृत विवरण:

- **कथन 1 सही है।** प्रस्तावना "हम भारत के लोग" से शुरू होती है, जो लोकप्रिय संप्रभुता का प्रतीक है। सर्वोच्च न्यायालय ने लगातार इसकी व्याख्या की है कि संप्रभुता सामूहिक रूप से जनता में निहित है और इसका प्रयोग संवैधानिक संस्थाओं के माध्यम से किया जाता है। हालाँकि कुछ संप्रभु कार्यो को प्रत्यायोजित (delegate) किया जा सकता है, लेकिन संप्रभुता स्वयं अविभाज्य और अहस्तांतरणीय है।
- **कथन 2 भी सही है।** अनुच्छेद 368 के तहत संवैधानिक संशोधन की शक्ति उसी घटक शक्ति से प्राप्त होती है जिसका प्रयोग संविधान सभा द्वारा किया गया था। हालाँकि अब संसद इस शक्ति का प्रयोग करती है, लेकिन वह इसे घटक प्राधिकरण (constituent authority) की निरंतरता के रूप में करती है, न कि सामान्य विधायी शक्ति के रूप में। इस अंतर को **केशवानंद भारती** जैसे मामलों में रेखांकित किया गया था, जिसमें यह माना गया था कि संविधान में संशोधन करते समय संसद एक घटक निकाय (constituent body) के रूप में कार्य करती है।

प्रश्न 2. निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त वाक्यांश "कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया" के संवैधानिक महत्व की सबसे अच्छी व्याख्या करता है?

- (a) संसद द्वारा अधिनियमित कोई भी प्रक्रिया मान्य है, चाहे उसकी निष्पक्षता कुछ भी हो
- (b) न्यायपालिका द्वारा व्याख्या की गई प्रक्रिया उचित, न्यायसंगत और गैर-मनमानी होनी चाहिए
- (c) प्रक्रिया को संविधान में वर्णित प्राकृतिक न्याय के अनुरूप होना चाहिए
- (d) प्रक्रिया को संसद और राज्य विधानसभाओं दोनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए

उत्तर: (b) न्यायपालिका द्वारा व्याख्या की गई प्रक्रिया उचित, न्यायसंगत और गैर-मनमानी होनी चाहिए

विस्तृत विवरण:

मूल रूप से, अनुच्छेद 21 की व्याख्या **ए.के. गोपालन** मामले में संकीर्ण रूप से की गई थी, जहाँ "कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया" का अर्थ विधायी रूप से अधिनियमित कोई भी प्रक्रिया थी। इस दृष्टिकोण को बाद में **मेनका गांधी** मामले में पलट दिया गया, जहाँ सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि ऐसी प्रक्रिया निष्पक्ष, न्यायसंगत और उचित होनी चाहिए, जिससे प्रभावी रूप से भारतीय संवैधानिक कानून में "उचित प्रक्रिया" (substantive due process) को शामिल किया गया। इस प्रकार, यह वाक्यांश अब विधायी मनमानी पर एक सीमा के रूप में कार्य करता है।

प्रश्न 3. मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. भाग III के तहत गारंटीकृत अधिकार केवल राज्य के विरुद्ध प्रवर्तनीय हैं, निजी व्यक्तियों के विरुद्ध नहीं।
2. अनुच्छेद 17 कार्यान्वयन कानून (implementing legislation) की आवश्यकता के बिना सीधे राज्य और निजी व्यक्तियों दोनों के विरुद्ध कार्य करता है।
3. सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक व्याख्या के माध्यम से कुछ मौलिक अधिकारों के "क्षैतिज अनुप्रयोग" (horizontal application) को मान्यता दी है।

उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

- (a) केवल एक
- (b) केवल दो
- (c) तीनों

(d) कोई नहीं

उत्तर: (b) केवल दो

विस्तृत विवरण:

- **कथन 1 गलत है।** जबकि अधिकांश मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध प्रवर्तनीय हैं, कुछ अधिकार—जैसे अनुच्छेद 15(2), 17 और 23—निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी क्षैतिज अनुप्रयोग (horizontal application) रखते हैं।
- **कथन 2 सही है।** अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और यह स्व-निष्पादक (self-executory) है, जो राज्य के साथ-साथ निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी सीधे कार्य करता है।
- **कथन 3 सही है।** सर्वोच्च न्यायालय ने व्याख्या के माध्यम से क्षैतिज प्रयोज्यता का विस्तार किया है, विशेष रूप से अनुच्छेद 21 और 15 से संबंधित मामलों में, निजी कार्यों में राज्य की जिम्मेदारी को पढ़कर जो मौलिक स्वतंत्रता को प्रभावित करते हैं।

प्रश्न 4. राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों (DPSP) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. वे गैर-न्यायोचित (non-justiciable) हैं लेकिन राजनीतिक जवाबदेही के माध्यम से संवैधानिक रूप से प्रवर्तनीय हैं।
2. संघर्ष की स्थिति में, मौलिक अधिकार हमेशा नीति निर्देशक सिद्धांतों पर हावी होते हैं।
3. संविधान राज्य को विशिष्ट नीति निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावी करने के लिए कुछ मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने की अनुमति देता है।
4. सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ नीति निर्देशक सिद्धांतों को संविधान की बुनियादी संरचना (basic structure) के अभिन्न अंग के रूप में माना है।

उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

- (a) केवल एक
- (b) केवल दो
- (c) केवल तीन
- (d) चारों

उत्तर: (c) केवल तीन

विस्तृत विवरण:

- **कथन 1 सही है।** नीति निर्देशक सिद्धांत अदालतों द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं, लेकिन शासन में बाध्यकारी हैं और लोकतांत्रिक एवं राजनीतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से प्रवर्तनीय हैं।
- **कथन 2 गलत है।** इनका संबंध श्रेणीबद्ध (hierarchical) नहीं है; सर्वोच्च न्यायालय ने विशेष रूप से **केशवानंद भारती** और **मिनर्वा मिल्स** के बाद "सामंजसपूर्ण निर्माण" (harmonious construction) के सिद्धांत को विकसित किया है।
- **कथन 3 सही है।** अनुच्छेद 31C और अन्य संवैधानिक प्रावधान निर्दिष्ट नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए कुछ मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगाने की अनुमति देते हैं।
- **कथन 4 सही है।** न्यायालय ने सामाजिक न्याय और कल्याणकारी अभिविन्यास जैसे सिद्धांतों को—जो नीति निर्देशक सिद्धांतों में परिलक्षित होते हैं—बुनियादी संरचना के हिस्से के रूप में मान्यता दी है।

प्रश्न 5. कथन - कारण प्रकार:

कथन (A): भारत में न्यायिक समीक्षा (judicial review) की शक्ति पूर्ण नहीं है और संवैधानिक संशोधन द्वारा इसे कम किया जा सकता है।

कारण (R1): संसद, घटक शक्ति का प्रयोग करते हुए, न्यायिक समीक्षा से संबंधित प्रावधानों सहित संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है।

कारण (R2): न्यायिक समीक्षा बुनियादी संरचना का हिस्सा है और इसलिए इसे संवैधानिक संशोधन द्वारा भी समाप्त नहीं किया जा सकता है।

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

- (a) A सत्य है; R1 सत्य है; R2 असत्य है
- (b) A असत्य है; R1 सत्य है; R2 सत्य है
- (c) A असत्य है; R1 असत्य है; R2 सत्य है
- (d) A सत्य है; R1 असत्य है; R2 सत्य है

उत्तर: (d) A सत्य है; R1 असत्य है; R2 सत्य है

विस्तृत विवरण:

- **कथन (Assertion) सत्य है** क्योंकि न्यायिक समीक्षा, मौलिक होने के बावजूद, संवैधानिक सीमाओं और प्रक्रियात्मक विनियमन के अधीन है। हालांकि, इसे पूरी तरह नष्ट नहीं किया जा सकता।
- **कारण 1 (R1) असत्य है** क्योंकि संसद की घटक शक्ति बुनियादी संरचना के सिद्धांत द्वारा सीमित है; वह संविधान में ऐसा संशोधन नहीं कर सकती जिससे न्यायिक समीक्षा समाप्त हो जाए।
- **कारण 2 (R2) सत्य है।** सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लगातार यह माना गया है कि न्यायिक समीक्षा बुनियादी संरचना का हिस्सा है, जिससे यह संवैधानिक संशोधन के माध्यम से भी पूर्ण विलोपन से मुक्त है।

दैनिक अभ्यास प्रश्न - करंट अफेयर्स अनुभाग से

प्रश्न 1. भारत द्वारा विकसित मैन-पोर्टेबल एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल (MPATGM) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. MPATGM एक 'इमेजिंग इन्फ्रारेड सीकर' का उपयोग करता है जो चलते हुए बख्तरबंद लक्ष्यों के खिलाफ भी वास्तविक 'दागो और भूल जाओ' (fire-and-forget) क्षमता प्रदान करता है।
2. MPATGM को केवल वाहनों पर लगे लॉन्च सिस्टम के साथ एकीकृत करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, न कि कंधे से दागो जाने वाले विन्यास (configurations) के लिए।

उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

- (a) केवल एक
- (b) दोनों
- (c) कोई भी नहीं
- (d) निर्धारित नहीं किया जा सकता

उत्तर: (a) केवल एक

विस्तृत विवरण:

- **कथन 1 सही है।** MPATGM एक इमेजिंग इंफ्रारेड (IIR) सीकर का उपयोग करता है, जो लॉन्च से पहले लक्ष्य को लॉक करने और स्वायत्त टर्मिनल मार्गदर्शन (autonomous terminal guidance) में सक्षम बनाता है। इसे ही वास्तविक 'दागो और भूल जाओ' क्षमता कहा जाता है।
- **कथन 2 गलत है।** MPATGM को विशेष रूप से एक 'मैन-पोर्टेबल' (मनुष्यों द्वारा ले जाने योग्य), कंधे से दागो जाने वाले सिस्टम के रूप में डिज़ाइन किया गया है, हालांकि बाद में ट्राइपॉड और वाहन एकीकरण की संभावना तलाशी जा सकती है। इसकी मुख्य विशेषता इन्फैंट्री (पैदल सेना) इकाइयों के लिए सुवाह्यता (portability) है।

प्रश्न 2. निम्नलिखित में से कौन सा ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (PSLV) को भारत के नए प्रक्षेपण यानों से सबसे बेहतर तरीके से अलग करता है?

- (a) यह पेलोड को केवल भू-स्थैतिक कक्षा (geostationary orbit) में रख सकता है
- (b) यह सभी चरणों में ठोस प्रणोदन (solid propulsion) का उपयोग करता है
- (c) इसने एक ही मिशन में बहु-कक्षीय तैनाती (multi-orbital deployment) का प्रदर्शन किया है
- (d) यह वाणिज्यिक उपग्रह प्रक्षेपण करने में असमर्थ है

उत्तर: (c) इसने एक ही मिशन में बहु-कक्षीय तैनाती (multi-orbital deployment) का प्रदर्शन किया है

विस्तृत विवरण:

PSLV ने एक ही मिशन में कई उपग्रहों को अलग-अलग कक्षाओं में स्थापित करने की क्षमता का बार-बार प्रदर्शन किया है, जो एक जटिल कार्य है और इसके लिए सटीक कक्षीय युद्धाभ्यास (orbital manoeuvring) की आवश्यकता होती है।

अन्य विकल्प गलत हैं: PSLV मुख्य रूप से GTO के लिए नहीं है, यह ठोस और तरल चरणों के मिश्रण का उपयोग करता है, और यह विदेशी उपग्रहों के लिए एक प्रमुख वाणिज्यिक प्रक्षेपण यान रहा है।

प्रश्न 3. वायुमंडलीय एरोसोल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. एरोसोल अपनी संरचना और ऊँचाई के आधार पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों 'रेडिएटिव फोर्सिंग' (radiative forcing) उत्पन्न कर सकते हैं।
2. सल्फेट एरोसोल आमतौर पर ग्रहीय एल्बेडो (planetary albedo) को बढ़ाकर सतह को ठंडा करने में योगदान करते हैं।

3. एरोसोल का वायुमंडलीय जीवनकाल कार्बन डाइऑक्साइड जैसी ग्रीनहाउस गैसों की तुलना में लंबा होता है।

उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

- (a) केवल एक
- (b) केवल दो
- (c) तीनों
- (d) कोई नहीं

उत्तर: (b) केवल दो

विस्तृत विवरण:

- **कथन 1 सही है।** एरोसोल वायुमंडल को या तो ठंडा कर सकते हैं (जैसे सल्फेट्स) या गर्म कर सकते हैं (जैसे ब्लैक कार्बन)।
- **कथन 2 सही है।** सल्फेट एरोसोल सौर विकिरण को बिखेरते हैं और बादलों की परावर्तकता (reflectivity) बढ़ाते हैं, जिससे शीतलन (cooling) होता है।
- **कथन 3 गलत है।** एरोसोल आमतौर पर दिनों से लेकर हफ्तों तक वायुमंडल में रहते हैं, जबकि CO₂ सदियों तक बना रहता है।

प्रश्न 4. पैक्स सिलिका पहल (Pax Silica Initiative) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसका उद्देश्य सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए एक ही भौगोलिक क्षेत्र पर वैश्विक निर्भरता को कम करना है।
2. यह एक बहुपक्षीय पहल है जिसमें लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्थाओं के बीच रणनीतिक सहयोग शामिल है।
3. भारत मुख्य रूप से 'डाउनस्ट्रीम' सेमीकंडक्टर डिजाइन और प्रतिभा पारिस्थितिकी तंत्र (talent ecosystem) में भागीदार है।

उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

- (a) केवल एक

(b) केवल दो

(c) तीनों

(d) कोई नहीं

उत्तर: (c) तीनों

विस्तृत विवरण:

- **कथन 1 सही है।** पैक्स सिलिका का लक्ष्य सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखलाओं को केंद्रित केंद्रों (concentrated hubs) से दूर ले जाकर विविधता लाना है।
- **कथन 2 सही है।** इसमें लचीली चिप आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित करने के लिए समान विचारधारा वाली, लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग शामिल है।
- **कथन 3 सही है।** भारत की ताकत उन्नत फैब्रिकेशन प्रभुत्व के बजाय चिप डिजाइन, मानव पूंजी और उभरती फैब्रिकेशन महत्वाकांक्षाओं में निहित है।

प्रश्न 5. परमाणु संलयन (nuclear fusion) अनुसंधान में 'ग्रीनवाल्ड लिमिट' (Greenwald Limit) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह प्लाज्मा घनत्व की एक ऊपरी सीमा को परिभाषित करता है जिसके आगे टोकामक (tokamak) संचालन अस्थिर हो जाता है।
2. यह सीमा प्लाज्मा करंट के सीधे आनुपातिक और टोकामक त्रिज्या (radius) के व्युत्क्रमानुपाती (inversely proportional) होती है।
3. ग्रीनवाल्ड सीमा से अधिक होने पर मुख्य रूप से प्लाज्मा का 'थर्मल रनवे' (thermal runaway) होता है।
4. यह सीमा केवल 'जड़त्वीय बंधन संलयन' (inertial confinement fusion) प्रणालियों के लिए प्रासंगिक है।

उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

(a) केवल एक

(b) केवल दो

(c) केवल तीन

(d) चारों

उत्तर: (b) केवल दो

विस्तृत विवरण:

- कथन 1 सही है। ग्रीनवाल्ड लिमिट स्थिर टोकामक प्लाज्मा बंधन (confinement) के लिए एक घनत्व दहलीज (threshold) निर्धारित करती है।
- कथन 2 सही है। अनुभवजन्य संबंध (empirical relation) घनत्व को प्लाज्मा करंट और मशीन के आकार से जोड़ता है।
- कथन 3 गलत है। सीमा का उल्लंघन करने से प्लाज्मा में व्यवधान (disruptions) उत्पन्न होते हैं, न कि थर्मल रनवे।
- कथन 4 गलत है। यह चुंबकीय बंधन (magnetic confinement/tokamak) प्रणालियों पर लागू होता है, जड़त्वीय बंधन पर नहीं।

प्रश्न 6. ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (PSLV) मिशनों के लिए उपयोग किया जाने वाला प्राथमिक प्रक्षेपण स्थल निम्नलिखित में से किस जलाशय (water body) के सबसे करीब स्थित है?

- (a) खंभात की खाड़ी
- (b) बंगाल की खाड़ी
- (c) अरब सागर
- (d) पाक जलडमरूमध्य

उत्तर: (b) बंगाल की खाड़ी

विस्तृत विवरण:

PSLV लॉन्च भारत के पूर्वी तट पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से होते हैं। यह प्रक्षेपण स्थल बंगाल की खाड़ी के सामने है, जो प्रक्षेपण के दौरान उपयोग किए गए चरणों और मलबे के सुरक्षित नीचे गिरने के लिए एक सुरक्षित प्रक्षेपवक्र (trajectory) प्रदान करता है।

दैनिक अभ्यास हेतु विषय आधारित प्रश्न

GS-I | विश्व इतिहास (World History)

प्रश्न 1. 19वीं शताब्दी में जर्मनी का एकीकरण केवल एक राष्ट्रवादी आंदोलन नहीं था, बल्कि शक्ति की राजनीति (power politics) का एक सुविचारित अभ्यास था।

जर्मन एकीकरण में 'रेयलपॉलिटिक' (यथार्थवादी राजनीति) की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

मॉडल उत्तर

1871 में जर्मनी का एकीकरण रोमानी राष्ट्रवाद की सहज अभिव्यक्ति कम और 'रेयलपॉलिटिक' (Realpolitik) में निहित एक सावधानीपूर्वक व्यवस्थित राजनीतिक रणनीति अधिक थी, विशेष रूप से ऑटो वॉन बिस्मार्क के नेतृत्व में। जबकि राष्ट्रवादी भावनाओं ने भावनात्मक वैधता प्रदान की, निर्णायक कारक कूटनीति, सैन्य शक्ति और नपी-तुली राज्यकला (statecraft) थे।

'रेयलपॉलिटिक' ने वैचारिक प्रतिबद्धताओं के बजाय व्यावहारिक विचारों पर जोर दिया। बिस्मार्क ने प्रशा (Prussia) के रणनीतिक हितों के लिए उदारवादी राष्ट्रवादी आकांक्षाओं को गौण बना दिया। उन्होंने सबसे पहले फ्रैंकफर्ट संसद के "वृहत जर्मनी" (Greater Germany) के उदारवादी दृष्टिकोण को दरकिनार कर आंतरिक विरोध को बेअसर किया और इसके बजाय ऑस्ट्रिया को छोड़कर प्रशा के नेतृत्व वाले "लघु जर्मनी" (Lesser Germany) को बढ़ावा दिया। इसने प्रशा का प्रभुत्व सुनिश्चित किया।

बाहरी रूप से, बिस्मार्क ने एक शत्रुतापूर्ण गठबंधन को सक्रिय किए बिना राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सीमित और नियंत्रित युद्धों की एक श्रृंखला तैयार की। **डेनमार्क युद्ध (1864)** ने कूटनीतिक रूप से डेनमार्क को अलग-थलग कर दिया, **ऑस्ट्रो-प्रशियन युद्ध (1866)** ने जर्मन मामलों से ऑस्ट्रिया को निर्णायक रूप से हटा दिया, और **फ्रैंको-प्रशियन युद्ध (1870-71)** ने एक साझा बाहरी खतरे के माध्यम से दक्षिणी जर्मन राज्यों को प्रशा के पीछे एकीकृत कर दिया। प्रत्येक संघर्ष से पहले प्रमुख यूरोपीय शक्तियों से तटस्थता या समर्थन सुनिश्चित करने के लिए कूटनीतिक तैयारी की गई थी।

'जोल्लवेरिन' (Zollverein) के माध्यम से आर्थिक एकीकरण ने जर्मन राज्यों के बीच अंतर्निर्भरता को बढ़ावा देकर प्रशा के नेतृत्व को और मजबूत किया, जिससे यह सिद्ध हुआ कि आर्थिक एकता राजनीतिक एकता से पहले आ सकती है। राष्ट्रवाद को एक साधन के रूप में इस्तेमाल किया गया, आदर्श के रूप में नहीं—लोकप्रिय भावनाओं को तब जुटाया गया जब वे उपयोगी थीं और जब वे असुविधाजनक थीं तो उन्हें नियंत्रित किया गया।

हालाँकि, रेयालपॉलिटिक-प्रेरित एकीकरण के दीर्घकालिक परिणाम हुए। नए जर्मन साम्राज्य की सत्तावादी प्रकृति लोकतांत्रिक राष्ट्रवाद के बजाय प्रशा के सैन्यवाद को दर्शाती थी। उदारवादी संस्थाओं को राजशाही और सैन्य अभिजात वर्ग के अधीन कर दिया गया, जिससे जर्मन राजनीतिक संस्कृति में संरचनात्मक सत्तावाद समाहित हो गया।

इस प्रकार, जर्मन एकीकरण यह दर्शाता है कि कैसे राष्ट्रवाद को सत्ता की राजनीति द्वारा आकार और दिशा दी जा सकती है। रेयालपॉलिटिक ने राष्ट्रवाद को नकारा नहीं, बल्कि इसे एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया, जिससे एक ऐसा एकीकृत जर्मनी बना जो शक्तिशाली और स्थिर था, लेकिन राजनीतिक रूप से रूढ़िवादी था—एक ऐसा परिणाम जिसने यूरोपीय इतिहास को गहराई से प्रभावित किया।

GS-II | शासन (Governance)

प्रश्न 2. सुशासन (Good governance) के मॉडल तेजी से विकेंद्रीकरण, पारदर्शिता और नागरिक-केंद्रित सेवा वितरण पर जोर दे रहे हैं।

उपयुक्त उदाहरणों सहित चर्चा कीजिए।

मॉडल उत्तर

सुशासन अब केवल कुशल प्रशासन तक सीमित नहीं है; यह तेजी से सहभागी, पारदर्शी और जवाबदेह शासन पर ध्यान केंद्रित करता है जो नागरिकों को सार्वजनिक सेवा वितरण के केंद्र में रखता है।

विकेंद्रीकरण, पारदर्शिता और नागरिक-केंद्रितता विश्व स्तर पर और भारत में आधुनिक शासन मॉडल के मुख्य स्तंभ हैं।

विकेंद्रीकरण निर्णय लेने की प्रक्रिया को नागरिकों के करीब लाकर संवेदनशीलता को बढ़ाता है। भारत में, 73वें और 74वें संशोधनों के माध्यम से पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक समर्थन ने स्थानीय समस्याओं के स्थानीय समाधानों को सक्षम बनाया है। केरल जैसे राज्य प्रदर्शित करते हैं कि कैसे वित्तीय और प्रशासनिक विकेंद्रीकरण सामाजिक परिणामों, विशेष रूप से स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार करता है।

भ्रष्टाचार को कम करने और विश्वास बढ़ाने के लिए **पारदर्शिता** महत्वपूर्ण है। सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम जैसे उपकरण शासन में खुलेपन को संस्थागत बनाते हैं। ऑनलाइन खरीद पोर्टल और 'ओपन डेटा' पहल जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म विवेकाधीन शक्तियों को कम करते हैं और नियम-आधारित निर्णय लेने को बढ़ावा देते हैं। पारदर्शिता नागरिकों को सरकारी कार्यों की जांच करने की अनुमति देकर 'पॉलिसी फीडबैक लूप' में भी सुधार करती है।

नागरिक-केंद्रित सेवा वितरण फोकस को नौकरशाही की सुविधा से हटाकर सार्वजनिक परिणामों पर ले जाता है। मिशन-मोड गवर्नेंस, सिंगल-विंडो क्लियरेंस और परिणाम-आधारित निगरानी जैसे मॉडल इस दृष्टिकोण

के उदाहरण हैं। तकनीक का उपयोग—जैसे डिजिटल पहचान प्रणाली और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT)—ने रिसाव (leakages) को कम किया है और सेवा की पहुंच में सुधार किया है, विशेष रूप से हाशिए पर रहने वाले समूहों के लिए।

विश्व स्तर पर, एस्टोनिया जैसे देश दर्शाते हैं कि कैसे डिजिटल शासन राज्य के साथ नागरिक संपर्क को सरल बना सकता है, जबकि लैटिन अमेरिका के कुछ हिस्सों में 'सहभागी बजटिंग' (participatory budgeting) दिखाती है कि कैसे नागरिक सीधे संसाधन आवंटन को प्रभावित कर सकते हैं।

हालाँकि, चुनौतियाँ बनी हुई हैं। क्षमता निर्माण के बिना विकेंद्रीकरण अक्षमता पैदा कर सकता है; जवाबदेही तंत्र के बिना पारदर्शिता सूचना के अतिभार (information overload) का परिणाम हो सकती है; और यदि डिजिटल साक्षरता असमान है तो डिजिटलीकरण से बहिष्करण का जोखिम बना रहता है।

निष्कर्षतः, सुशासन मॉडल तब सफल होते हैं जब संस्थागत सुधारों को प्रशासनिक क्षमता, राजनीतिक प्रतिबद्धता और नागरिक सशक्तिकरण द्वारा पूरक बनाया जाता है। शासन का भविष्य समावेशी, पारदर्शी और संवेदनशील प्रशासन के लिए तकनीक का लाभ उठाते हुए लोकतांत्रिक जुड़ाव को गहरा करने में निहित है।

GS-III | विज्ञान और नैतिकता (Science and Ethics)

प्रश्न 3. वैज्ञानिक उन्नति नैतिक रूप से तटस्थ होती है, लेकिन इसका अनुप्रयोग (application) नहीं।

उभरती प्रौद्योगिकियों के संदर्भ में इस कथन का परीक्षण कीजिए।

मॉडल उत्तर

विज्ञान, ज्ञान की एक व्यवस्थित खोज के रूप में, नैतिक रूप से तटस्थ है; हालाँकि, वैज्ञानिक ज्ञान का अनुप्रयोग गहराई से मूल्यों पर आधारित होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), बायोटेक्नोलॉजी और परमाणु ऊर्जा जैसी उभरती प्रौद्योगिकियाँ इस बात का उदाहरण हैं कि कैसे वैज्ञानिक खोजें समाज के साथ जुड़ते ही नैतिक विचार केंद्रीय हो जाते हैं।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) दक्षता बढ़ा सकता है, स्वास्थ्य सेवा निदान में सुधार कर सकता है और संसाधन उपयोग को अनुकूलित कर सकता है। साथ ही, यह निगरानी (surveillance), एल्गोरिदम पूर्वाग्रह (bias), रोजगार विस्थापन और गोपनीयता के क्षरण से संबंधित नैतिक चिंताएं पैदा करता है। तकनीक स्वयं तटस्थ है; नैतिक दुविधाएं इस बात से उत्पन्न होती हैं कि समाज इसे कैसे तैनात और विनियमित करने का विकल्प चुनते हैं।

बायोटेक्नोलॉजी इसी तरह के तनाव प्रस्तुत करती है। CRISPR जैसे जीन-एडिटिंग उपकरण आनुवंशिक रोगों के संभावित उपचार प्रदान करते हैं लेकिन 'यूजेनिक्स' (eugenics), 'डिजाइनर बेबी' और असमान पहुंच के बारे में चिंताएं भी पैदा करते हैं। नैतिक पर्यवेक्षण के बिना, वैज्ञानिक क्षमता नैतिक सहमति से आगे निकल सकती है, जिससे अपरिवर्तनीय सामाजिक परिणाम हो सकते हैं।

परमाणु विज्ञान इस द्वैत को और स्पष्ट करता है। परमाणु विखंडन ने स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को सक्षम किया है लेकिन सामूहिक विनाश के हथियार भी बनाए हैं। नैतिक जिम्मेदारी परमाणु प्रतिक्रियाओं की खोज में नहीं, बल्कि प्रसार, निवारण (deterrence) और नागरिक उपयोग से संबंधित नीतिगत विकल्पों में निहित है।

नैतिकता एक मार्गदर्शक ढांचे के रूप में कार्य करती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वैज्ञानिक अनुप्रयोग मानवीय मूल्यों जैसे कि गरिमा, न्याय और स्थिरता के साथ मेल खाते हों। 'एहतियाती सिद्धांत' (precautionary principle), 'सूचित सहमति' और 'अंतर-पीढ़ीगत समानता' जैसी अवधारणाएं तकनीकी उपयोग के प्रबंधन में महत्वपूर्ण हो जाती हैं।

इसलिए, विज्ञान के नैतिक शासन के लिए बहु-विषयक जुड़ाव की आवश्यकता है—वैज्ञानिकों, नीति निर्माताओं, नीतिशास्त्रियों और नागरिकों को मिलकर मानदंडों और विनियमों को आकार देना चाहिए। एथिकल रिव्यू बोर्ड, तकनीकी प्रभाव मूल्यांकन और वैश्विक संधियाँ जैसे संस्थागत तंत्र एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

निष्कर्षतः, जबकि विज्ञान मानवीय क्षमता का विस्तार करता है, नैतिकता को मानवीय पसंद को आकार देना चाहिए। नैतिक आधार के बिना प्रगति उसी कल्याण को कमजोर करने का जोखिम उठाती है जिसे वैज्ञानिक उन्नति बढ़ावा देना चाहती है।

GS-IV | नीतिशास्त्र (Ethics)

प्रश्न 4. सत्यनिष्ठा (Integrity) की परीक्षा तब नहीं होती जब चुनाव आसान होते हैं, बल्कि तब होती है जब व्यक्तिगत कीमत सार्वजनिक कर्तव्य के साथ टकराती है।

उदाहरणों के साथ चर्चा कीजिए।

मॉडल उत्तर

सत्यनिष्ठा मूल्यों, शब्दों और कार्यों के बीच निरंतरता का प्रतिनिधित्व करती है, विशेष रूप से तब जब नैतिक आचरण के लिए व्यक्तिगत बलिदान की आवश्यकता होती है। सार्वजनिक जीवन में, सत्यनिष्ठा का सबसे सार्थक परीक्षण तब होता है जब व्यक्तियों को ऐसी दुविधाओं का सामना करना पड़ता है जहाँ नैतिक सिद्धांतों का पालन करने से पेशेवर, सामाजिक या व्यक्तिगत नुकसान उठाना पड़ता है।

सार्वजनिक अधिकारियों को राजनीतिक हस्तक्षेप से लेकर संस्थागत जड़ता तक के दबावों का सामना करना पड़ता है। ऐसी परिस्थितियों में सत्यनिष्ठा बनाए रखने के लिए **नैतिक साहस (moral courage)** की आवश्यकता होती है—स्वार्थ के ऊपर जनहित को प्राथमिकता देने की इच्छा। 'व्हिसलब्लोअर्स' (Whistleblowers) इस संघर्ष का उदाहरण हैं; गलत कामों को उजागर करने से अक्सर प्रतिशोध, करियर में ठहराव या सामाजिक अलगाव होता है, फिर भी यह संस्थागत जवाबदेही के लिए आवश्यक बना रहता है।

सत्यनिष्ठा में सूक्ष्म नैतिक क्षरण का विरोध करना भी शामिल है। सुविधा के लिए मामूली प्रक्रियात्मक उल्लंघनों को स्वीकार करना धीरे-धीरे कदाचार को सामान्य बना सकता है। नैतिक प्रशासक लगातार नियमों का पालन करके सत्यनिष्ठा प्रदर्शित करते हैं, भले ही छोटे रास्ते (shortcuts) तत्काल लाभ या अनुमोदन का वादा करते हों।

ऐतिहासिक और समकालीन उदाहरण दिखाते हैं कि सत्यनिष्ठा लंबे समय में संस्थानों को मजबूत करती है। जो नेता नैतिक जिम्मेदारी पर इस्तीफा दे देते हैं—भले ही कानूनी बाध्यता न हो—वे लोकतांत्रिक जवाबदेही को सुदृढ़ करते हैं। इसके विपरीत, समझौता की गई सत्यनिष्ठा जनता के विश्वास को खत्म करती है और शासन की वैधता को कमजोर करती है।

सत्यनिष्ठा को नैतिक जागरूकता, सहायक संस्थागत संस्कृति और व्यक्तिगत नैतिक आधार के माध्यम से बनाए रखा जाता है। आचार संहिता, नैतिक प्रशिक्षण और पारदर्शी प्रणालियाँ नैतिक कार्रवाई के व्यक्तिगत बोझ को कम करती हैं। हालाँकि, अंततः, सत्यनिष्ठा चरित्र में निहित एक व्यक्तिगत पसंद है।

निष्कर्षतः, सत्यनिष्ठा प्रलोभन की अनुपस्थिति नहीं है बल्कि उस पर विजय है। समाज तब प्रगति करता है जब व्यक्ति व्यक्तिगत आराम के ऊपर नैतिक कर्तव्य चुनते हैं, यह पुष्टि करते हुए कि नैतिक साहस प्रभावी और भरोसेमंद शासन की नींव है।

समसामयिकी (Current Affairs)

प्रश्न 5. 'भाषिणी समुदाय' (BHASHINI Samudaye) केवल डिजिटल समावेश से भाषाई सशक्तिकरण की ओर एक बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है।

इसके महत्व और चुनौतियों का परीक्षण कीजिए।

मॉडल उत्तर

'भाषिणी समुदाय' एक बुनियादी बाधा-भाषा-को संबोधित करके भारत के डिजिटल शासन में एक परिवर्तनकारी कदम का प्रतीक है। जबकि डिजिटल बुनियादी ढांचे का तेजी से विस्तार हुआ है, भाषाई बहिष्करण ने आबादी के बड़े वर्गों के लिए सार्थक पहुंच को सीमित कर दिया है। भाषिणी समुदाय भारतीय

भाषाओं में एआई-संचालित भाषाई उपकरणों को सक्षम करके डिजिटल स्थानों के लोकतंत्रीकरण का प्रयास करता है।

इसका महत्व तीन आयामों में है। **पहला**, यह नागरिकों को अपनी मातृभाषा में डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ बातचीत करने में सक्षम बनाकर सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच बढ़ाता है, जिससे लोकतांत्रिक भागीदारी गहरी होती है। **दूसरा**, यह छोटे व्यवसायों, किसानों और अनौपचारिक श्रमिकों को भाषाई नुकसान के बिना बाजारों और जानकारी तक पहुंचने के लिए सशक्त बनाकर आर्थिक समावेशन का समर्थन करता है। **तीसरा**, यह भारतीय भाषाओं को उभरते डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र में एकीकृत करके सांस्कृतिक संरक्षण को मजबूत करता है।

इस पहल का सहयोगी मॉडल—सरकार, स्टार्टअप, शिक्षा जगत और ओपन-सोर्स समुदायों को एक साथ लाना—भाषा डेटा पर एकाधिकार नियंत्रण से बचते हुए नवाचार को बढ़ावा देता है। यह "समुदाय-प्रथम" दृष्टिकोण इसे पूरी तरह से ऊपर से नीचे (top-down) वाली डिजिटल पहलों से अलग करता है।

हालाँकि, चुनौतियाँ बनी हुई हैं। भाषाई विविधता विशाल है, और बोलियों (dialects) के बीच गुणवत्ता, संदर्भगत सटीकता और समावेशिता सुनिश्चित करना जटिल है। भाषाई डेटासेट में पूर्वाग्रह छोटे भाषाई समुदायों को हाशिए पर धकेल सकता है। डेटा गोपनीयता, बौद्धिक संपदा अधिकार और ओपन मॉडल की दीर्घकालिक स्थिरता के लिए भी सावधानीपूर्वक शासन की आवश्यकता है।

इसके अलावा, तकनीकी समावेशन को डिजिटल साक्षरता और उपकरणों (devices) तक सस्ती पहुंच द्वारा पूरक होना चाहिए; अन्यथा, अकेले भाषाई उपकरण डिजिटल विभाजन को पाट नहीं सकते।

निष्कर्षतः, भाषिणी समुदाय पहुंच-आधारित समावेशन से क्षमता-आधारित सशक्तिकरण की ओर एक बदलाव को दर्शाता है। यदि इसे नैतिक सुरक्षा उपायों, सामुदायिक भागीदारी और संस्थागत समर्थन के साथ लागू किया जाता है, तो यह बहुभाषी समाजों में डिजिटल शासन को फिर से परिभाषित कर सकता है।